

समस्या को हल करने में विशेष दिलचस्पी से जिम्मेदारी लेकर दोनों अणु बिजली घर की इकाइयों को अनुभवी वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा सुचारु रूप से चलाने में सक्रिय कदम उठाकर राजस्थान प्रान्त की जनता को इस संकटमय घड़ी में उबार कर अपने आवश्यक कर्तव्य को निभावें।

(ii) NEED FOR INQUIRY INTO FAKE ENCOUNTERS WITH DACOITS IN U.P. RESULTING IN KILLING OF INNOCENT PERSONS.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि लोग अपने को पूर्णतः असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डाकुओं का सफाया करने के नाम पर वहां की पुलिस ने डाकुओं से फर्जी मुठभेड़ का बहाना बनाकर सैकड़ों की संख्या में गरीब और निर्दोष लोगों को पकड़ कर गोली मार दी है और यह क्रम आज भी जारी है। पुलिस लोगों को उनके घरों से या रास्ते से पकड़ कर ले जाती है और रात को किसी गांव के पास अथवा जंगल में ले जाकर उनको गोली मार देती है और इस बात का भूठा नाटक रचती है कि डाकुओं से मुठभेड़ में डाकू मारे गए हैं। ऐसे मारे जाने वालों में बड़ा बहुमत पिछड़े-वर्गों, हरिजन और मुसलमान, दूसरे वर्गों के कुछ गरीब लोग भी हैं। इस प्रकार का भूठी मुठभेड़ का बहाना बनाकर लोग मारे गए हैं। इससे पूरे प्रदेश में आतंक छाया हुआ है और भय का वातावरण बन गया है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह अपराधी भी है तो उस पर मुकदमा चलाए बिना, उसको बगैर अपनी सफाई का मौका दिए बिना पकड़ कर गोली मारना मानवीय अधिकारों के विपरीत है और ऐसी घटनायें केवल उसी देश और समाज में हो सकती हैं जहां कानून

और व्यवस्था के लिए कोई आदर न हो और जंगली राज्य हो। दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित डाकुओं के गिरोह उत्तर प्रदेश में लोगों को घरों में, रेल गाड़ी में, बसों में लूट रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश का शासन इन डकैतों पर काबू पाने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाली इस प्रकार की हत्याओं की उच्चतम न्यायालय के जज से जांच कराई जाये। इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें दण्ड दिया जाए और केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल इस बात का आदेश दे कि वह फर्जी मुठभेड़ के नाम पर लोगों की हत्यायें बन्द करें।

15 hrs.

(iii) SHORTAGE OF KEROSENE OIL IN GHAZIPUR DISTRICT IN UTTAR PRADESH.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का दौरा कर रहा था तो मुझे हर जगह यह शिकायतें मिलीं कि मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ब्लैक में मिट्टी का तेल ढाई रुपये से लेकर पांच रुपये तक बिकता है जब कि उसका दाम दो रुपये से भी कम है।

मिट्टी का तेल न मिलने के कारण विशेषकर गांव के लोगों में बड़ा क्षोभ है। मैं समझता हूँ कि मिट्टी का तेल आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन फिर भी गाजीपुर में मिट्टी का तेल न मिलने से बड़ा आश्चर्य होता है।

[श्री जंजुल बशर]

मिट्टी का तेल न मिलने की तथा उसको ब्लैक पर बेचे जाने की शिकायतें बहुत हैं जो कि मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिली हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी के तेल का वितरण सहकारी भण्डारों तथा कुछ लाइसेंस शुदा वितरकों से कराती है। अनेक स्थानों पर मैंने यह पाया कि ये वितरक और कोआपरेटिव भण्डार मिट्टी का तेल नहीं रख रहे हैं। कमी होने के कारण जो भी तेल उपलब्ध होता है वह ब्लैक में बिक जाता है।

मेरा पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री से आग्रह है कि वह गाजीपुर में अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल पहुँचाने की व्यवस्था करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दें कि इसे कण्ट्रोल से मुक्त किया जाये ताकि पहले की तरह गांव से लेकर शहर तक दुकानों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके।

(iv) CRISIS IN COTTON MILLS

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack); I would like to raise the following issues under Rule 377.

A large number of cotton mills of the country are on the verge of closure due to demand recession. Huge stocks of cotton cloth are piling up and the financial position of those mills is deteriorating. Most of the mills are working below their capacity. The periodic labour unrest is another reason for the crisis in the cotton mills particularly in the northern region of the country. Almost all mills in this region are incurring losses due to steep rise in the prices of cotton and other inputs. Coal has to be moved by road and diesel generating sets are being used in the wake of power cuts, thereby adding to the production cost.

In view of the crisis, the proposal for modernisation of cotton mills has been pushed to the background. If remedial measures are not taken by the Government on a priority basis, the crisis faced by the textile industry will deepen further.

Therefore, the Government should relax credit norms to provide some relief to the mills. It is necessary to ensure supply of cotton and viscose fibre at stable and reasonable prices so that the production cost could be reduced. Proper incentives should be given for boosting the export of fabrics. At the same time, immediate steps should be taken by the Government of India to abolish import duty on viscose staple fibre and reduce the countervailing excise in order to ensure economic working of cotton mills and to save them from closure.

(v) NEED FOR SETTING UP A FISHING HARBOUR AT PARADIP PORT

SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur): The authority of Paradip Port of Orissa is facing a great difficulty in accommodating a large number of boats in the absence of a fishing harbour. About 500 mechanised and non-mechanised boats are operating in the Paradip area and those boats are being accommodated temporarily at wooden jetties in a very limited space inside the turning basin of the main harbour. The facility available for accommodating those boats is very inadequate.

The proposal to set up a fishing harbour at Paradip Port has been pending before the Government as far back as 1970. The estimated cost of the proposed fishing harbour has been updated from time to time. The Government of Orissa and the Paradip Port authority have requested the Centre to take up construction work of the fishing harbour at Paradip at an early date.